भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा व्यापार मेलों का आयोजन

1747. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:**
श्री राम जेठमलानी:
क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय व्यापार मेला, प्राधिकरण द्वारा देश-विदेश में अनेकों व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन किया गया;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन देशों में ये आयोजन किये गये, उनके नाम क्या हैं; और

(ग) इन आयोजनों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई, इन प्रदर्शनियों, मेलों आदि में कुल कितने सामान की बिक्री हुई और इनके द्वारा देश ने कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल **श्रीधरन**): (क) जी, हां।

(ख) जिन देशों में इन व्यापार मेलों का आयोजन किया गया, वे इस प्रकार हैं; फ्रांस, इटली, जापान, जिम्बाबवे, यूगोस्लाविया, संघीय जर्मन गणराज्य, केन्या, ईराक, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मन जनवादी गणराज्य, घाना, थाईलैण्ड, अमरीका, हांगकांग, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अफगानिस्तान, कनाडा, कैमरून, बहरीन, मलयेशिया, नेपाल, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, दक्षिण कोरिया, सेनेगल, सोवियत संघ, मारिशस, चीन, सीरिया, ईरान, वेनेजुएला तथा जोर्डन।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन क्रियाकलापों के आयोजन में हुआ कुल खर्च तथा बुक किया गया कारोबार इस प्रकार रहा:

(लाख रुपयों में)

वर्ष	खर्च*	बुक किया गया कारोबार
1987-88	1,038	20,716
1988-89	1,408	38,364
1989-90	1,642	49,184

(* अनन्तिम)

अर्द्ध परिसाधित इस्पात पर शुल्क का घटाया जाना

1748. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में अर्द्ध परिसाधित इस्पात उत्पादों (सेमीफिनिश्ड स्टील प्रोडक्ट्स) पर शुल्क कम किए जाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में इस्पात की कमी को देखते हुए अनेकों संबंधित चीजों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के संबंध में, सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गयी है; और

(ग) यदि इस संबंध में कोई योजना नहीं बनाई गयी है, तो उसके क्या कारण है?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय **का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी)**: (क) संसद में पेश किए गए बजट में अर्ध-तैयार-इस्पात मदों के संबंध में सीमा-शुल्क में कमी करने का प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग) गौण इस्पात क्षेत्र में अर्ध-तैयार-इस्पात के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

विशाखापतनम इस्पात कारखाने में पानी उपलब्ध न होने के कारण उत्पादन आरंभ होने में विलंब

1749. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सच है कि विशाखापटनम इस्पात कारखाने में उत्पादन कार्य में विलम्ब होने का मुख्य कारण पानी का समुचित मात्रा में उपलब्ध न होना है;

(ख) क्या पेलेरू नदी से पानी उपलब्ध कराए जाने की कोई योजना थी;

(ग) यदि हां, तो कारखाने के लिए पानी उपलब्ध कराने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में कार्य के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी): (क) धमन भट्टी नं०-1 को चालू करने में विलम्ब का मुख्य कारण पानी न मिलना था।

(ख) जी, हां। (येलेरू नदी से न कि पेलेरू नदी से)।

(ग) अप्रत्याशित भूवैज्ञानिक समस्याएं तथा कुछ ठेकेदारों का असंतोषजनक कार्य निष्पादन।

(घ) जुलाई/अगस्त, 1990।

NRI investments in capital issues

1750. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the *Financial Express* of the 10th May, 1990 regarding NRI investments in capital issues; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) Yes, Sir.

(b) Investor response to the issue of a company depends upon a variety of factors, including the general state of the capital market, the marketing effort put in by the company, its past record, the expectations and perception of the investors, and other options available to them.

Representations received by Indian Overseas Bank's Zonal Offices at Calcutta and Madras

1751. PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: WiU the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the» Indian Overseas Bank's Zonal Offices at Calcutta and Madras have received number of representations from various constituents who were stuck up with payments problems with some public sector units for waiving of interest charges;

(b) whether the Bank has been •sympathetic to such claims;

(c) whether any concrete steps have been taken by the Bank to initiate discussions with concerned public sector units;

(d) if so, what are the details thereof; and

(e) what further steps are being taken to resolve the issues?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) Indian Overseas Bank (IOB) has reported that its Zonal Office, Madras has not received any representation from any of their constituents for waiver of interest due to problems with public sector undertakings. Similarly, the Zonal Office of IOB at Calcutta has not reported the initiation of any such discussions.

(b) to (e) Do not arise.

Bungling in tax payment by persons engaged in lottery business

1752. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the details of organisations engaged in the lottery business which were found to have been evading tax payments in the recent past as observed by the C&AG in his annual report of 1988-89; and

(b) whether Government propose to take any penal action against these organisations and if so, what are the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) Relevant information is being collected from the field officers of the Income-tax Department and will be laid on the Table of the House in due course.

(b) Appropriate action (including penal action) wherever required will be taken according to law in the case of those who are found to have evaded tax.

Steps to curb smuggling by sea and air.

1753. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state: